



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2019/भाद्र 27, 1941
No. 285] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2019/BHADRA 27, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2019

मामला सं. ओआई – 14/2019

विषय – सउदी अरब साम्राज्य और संयुक्त अरब अमीरात (यू ए ई) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्सीबल स्लैबस्टॉक पॉलीओल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत ।

1. **फा.सं. 6/20/2019-डीजीटीआर :** वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां इसके बाद अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण अथवा पाटित वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिन्हें इसके बाद ए.डी. नियमावली कहा गया है) के संबंध में ।
2. मै. मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमि. ने सउदी अरब साम्राज्य और संयुक्त अरब अमीरात (यू ए ई) (जिन्हें यहां इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्सीबल स्लैबस्टॉक पॉलीओल (जिन्हें यहां संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में मूल जांच की शुरुआत के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद ए.डी. नियमावली कहा गया है) के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है ।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पोलीओल है। संबद्ध उत्पाद एक ट्रायलॉन चैन स्टार्टर के साथ प्रोपेलीन ऑक्साइड और इथेलीन ऑक्साइड के साथ पॉलीमराइजेशन द्वारा विनिर्मित 3000-4000 आणविक भारांश वाला एक स्पष्ट चिपचिपा द्रव पदार्थ (विस्कॉस लिक्विड पॉलीमर) है। यह एक पॉलीथर है और जो उत्प्रेरक (कैटालिस्ट) और योजक (एडीटिव्स) के साथ प्रतिक्रिया पर अपहोलीस्टरी, मैट्रेसिज, पिलोज, बोलस्टर्स, ट्रांसपोर्ट सीटिंग और पैकेजिंग में प्रयुक्त होने वाला पोलीयुरेथिन फोम उत्पन्न करता है। फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पोलीओल (जिसे यहां “संबद्ध वस्तु” कहा गया है) का टैंकर्स में आवागमन किया जाता है अथवा स्टील के ड्रमों में संग्रहित किया जाता है।
4. संबद्ध वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय-39 और इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार “प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुओं” के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

5. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तुएं, जो भारत में पाटित की जा रही हैं, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के सदृश हैं। पाटित वस्तुओं और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा आवेदक द्वारा उत्पादित विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद में न तो तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता, कार्यों के संबंध में और न ही अंतिम प्रयोग के संबंध में कोई अंतर है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए ए डी नियमावली के अंतर्गत इन्हें “संबद्ध वस्तुएं” माना जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और ‘स्थिति’

6. आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि. द्वारा दायर किया गया है। जैसाकि मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दावा किया गया है, वे भारत में संबद्ध वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक हैं और इसलिए, नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग संस्थापित हैं और आवेदन ऊपर बताई गई नियमावली के नियम 5 (3) की शर्तों में खरा उतरने के मापदंड को भी पूरा करता है।

घ. शामिल देश

7. जांच में शामिल देश सउदी अरब साम्राज्य और संयुक्त अरब अमीरात (यू ए ई) हैं (जिन्हें यहां इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है)।

ङ. सामान्य मूल्य

8. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। सामान्य मूल्य को सर्वोत्तम प्राप्त सूचना के अनुसार कच्ची सामग्री की लागत, परिवर्तन लागत और अन्य व्ययों के आधार पर निर्मित किया गया है।

च. निर्यात कीमत

9. याचिकाकर्ताओं ने डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। कीमत समायोजन का दावा समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन हैंडलिंग और निकासी प्रभारों, कमीशन, ऋण लागत के कारण किया गया है।

छ. पाटन मार्जिन

10. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखानागत स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथमदृष्टया संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन को दर्शाते हैं। इसके पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का

सामान्य मूल्य कारखानागत निर्यात कीमत की तुलना में ऊंचा है जो प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुएं पाटित की जा रही हैं।

ज. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

11. आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदकों ने कुल रूप में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप सामना की गई क्षति और भारत में उत्पादन और खपत, कीमत में कटौती, कीमत से कम कीमत पर बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। एक पाटनरोधी जांच को आरंभ करने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही 'क्षति' के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य विद्यमान हैं।

झ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

12. और जबकि प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया पाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के पर्याप्त साक्ष्य हैं और पाटनरोधी जांच की शुरुआत का औचित्य सिद्ध करने के लिए घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, प्राधिकारी कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की सिफारिश करने, जो यदि लागू होता तो घरेलू उद्योग की 'क्षति' को दूर करने के लिए पर्याप्त होता, एतद्वारा, नियमावली के नियम 5 की शर्तों में कथित पाटन और घरेलू उद्योग की परिणामी क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं।

ट. जांच की अवधि

13. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 (12 महीने है) तथापि, क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ, पिछले तीन वर्षों के आंकड़े अर्थात् अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016, अप्रैल, 2016 से मार्च 2017 और अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 और जांच की अवधि (पी ओ आई) पर विचार किया गया है।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे दिए गए पते पर निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं बताए गए तरीके से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ड. हितबद्ध पक्षकारों के पंजीकरण और उत्तर दायर करने की समय-सीमा

16. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा

पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

17. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस पत्र के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार, जिनका पता उपलब्ध नहीं है, वे भी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियां/सूचना दर्ज करा सकते हैं।

च. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।
19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की चार (04) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (02) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
20. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।
21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/ रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
23. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।
24. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।
25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2019

Case No. OI - 14/2019

Subject : Initiation of an Anti-dumping investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol originating in or exported from the Kingdom of Saudi Arabia and United Arab Emirates (UAE).

1. **F.No. 6/20/2019-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules).
2. M/s Manali Petrochemicals Ltd., has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from Kingdom of Saudi Arabia and United Arab Emirates (UAE) (hereinafter referred to as the subject countries).

A. Product under consideration

3. The product under consideration in the present investigation is Flexible slabstock polyol. The subject product is a clear viscous liquid polymer of molecular weight 3000-4000, manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives yields polyurethane foams used in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport seating and packaging. Flexible slabstock polyol is transported in tankers or stored in steel drums (hereinafter referred to as the “subject goods”).
4. The subject goods are classified under the category “Plastics and articles thereof” in Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 3907 20 as per International Trade Classification. The classification, however, is only indicative and in no way binding on the scope of the present investigation.

B. Like Article

5. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

C. Domestic Industry & ‘Standing’

6. The Application has been filed by M/s. Manali Petrochemicals Ltd on behalf of the domestic industry. As claimed by M/s. Manali Petrochemicals Ltd, they are the major producer of the subject goods in India and therefore constitute the domestic industry within the meaning of the Rules 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

D. Countries involved

7. The countries involved in the investigation are Kingdom of Saudi Arabia and United Arab Emirates (UAE) (hereinafter referred to as the subject countries).

E. Normal value

8. The Petitioners have claimed that they were not able to obtain reliable information in relation to prices of subject goods in the subject countries. The normal value has been constructed based on raw material cost, conversion cost and other expenses as per best available information.

F. Export Price

9. The Petitioners have claimed export price on the basis of data published by DGCIS. Price adjustments have been claimed of account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, port handling and clearance charges, commission, credit cost.

G. Dumping Margin

10. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie show dumping margin in respect of the subject goods from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

H. Injury and Causal Link

11. Information furnished by the petitioner has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The petitioner has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price suppression, price underselling, capacity utilization, profitability, cash profits and return on capital employed. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

I. Initiation of Anti-Dumping investigation.

12. And whereas the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

J. Period of Investigation

13. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2018 to 31st March 2019 (12 months). However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. April 2015 to March 2016, April 2016 to March 2017, April 2017 to March-2018 and the period of investigation (POI) has been considered.

K. Submission of information

14. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,
Directorate General of Trade Remedies,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5, Parliament Street, New Delhi -110001.**

15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

L. Time Limit for Registration of Interested Parties and Filing of Response

16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.
17. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/information within 40 days from date of publication of this notification.

M. Submission of Information on Non-Confidential basis

18. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be

- submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either “confidential” or “non-confidential” at the top of each page.
19. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Four (4) copies of the confidential version and two (04) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
 20. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
 21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
 22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
 23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information. Inspection of Public File
 24. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties. Non-cooperation
 25. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General